पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग),

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली, कार्तिक 08, 1945

सोमवार, अक्टूबर 30, 2023

हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक ढांचे आवश्यक: चौथे गोवा समुद्री सम्मेलन में रक्षा मंत्री

स्वतंत्र और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का किया आह्वान

श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थायी प्रथाओं पर मिलकर काम करने का किया आग्रह

"अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने से निपटने के लिए निगरानी डेटा साझा करना आज के समय की आवश्यकता है"

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, समुद्री डकैती, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अत्यधिक मछली पकड़ने और उच्च समुद्र में वाणिज्य की स्वतंत्रता जैसी समुद्री चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक शमन ढांचे की स्थापना का आह्वान किया है। वह अक्टूबर 30 , 2023 को गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (जीएमसी) के चौथे संस्करण में मुख्य भाषण दे रहे थे।

अक्टूबर 29, 2023 को शुरू हुए इस तीन दिवसीय सम्मेलन में कोमोरोस के रक्षा प्रभारी प्रतिनिधि श्री मोहम्मद अली यूसूफा और नौसेना के प्रमुख/समुद्री बलों के प्रमुख/ग्यारह अन्य हिंद महासागर देशों - बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र को कम सुरक्षित और कम समृद्ध बनाने वाले स्वार्थी हितों से बचकर साझा समुद्री प्राथमिकताओं को सहकारी रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) 1982 में प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, 'एक स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था हम सभी के लिए प्राथमिकता है। 'शक्ति ही सही है' इस तरह के आदर्शों की समुद्री व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का पालन हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारे संकीर्ण तात्कालिक हित हमें स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन या अवहेलना करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारे सभ्य समुद्री संबंध टूट जाएंगे। हमारी साझा सुरक्षा और समृद्धि तब तक संरक्षित नहीं की जा सकती जब तक कि हम सभी समुद्री नियमों का सहकारी रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध न हों। सहयोग को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी देश दूसरों पर आधिपत्य के तरीके से हावी न हो, जुड़ाव के उचित नियम महत्वपूर्ण हैं।

जलवायु परिवर्तन पर, रक्षा मंत्री ने कहा कि सहयोगात्मक शमन ढांचे में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं के लिए मिलकर काम करने वाले देशों को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समस्या से उबर सकती है यदि सभी देश हरित अर्थव्यवस्था में निवेश करके उत्सर्जन में कटौती करने की जिम्मेदारी स्वीकार करें और जरूरतमंद देशों के साथ प्रौद्योगिकी और पूंजी साझा करें।

श्री राजनाथ सिंह ने अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने का भी उल्लेख किया, जो एक चुनौती है जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन से संबंधित है। "आईयूयू मछली पकड़ने से महासागर पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ मत्स्य पालन खतरे में पड़ता है। यह हमारी आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है। निगरानी डेटा के संकलन और साझा करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी प्रयास समय की आवश्यकता है। यह अनियमित या धमकी भरे व्यवहार वाले तत्वों की पहचान करने में मदद करेगा, जिसका दृढ़ता से मुकाबला करना होगा।

इन शमन ढांचे को लागू करने के लिए, रक्षा मंत्री ने सहयोग और राष्ट्रों के बीच संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ और सभी राष्ट्रों के प्रबुद्ध स्वार्थ के आधार पर पारस्परिक लाभ के बीच अंतर को समझाते हुए इसे और विस्तार से बताया। "सर्वोत्तम परिणाम में अक्सर राष्ट्रों के बीच सहयोग और विश्वास का निर्माण शामिल होता है, लेकिन शत्रुतापूर्ण दुनिया में अकेले लाभ उठाने या कार्य करने का डर हानिकारक निर्णयों को जन्म दे सकता है। चुनौती ऐसे समाधान खोजने की है जो सहयोग को बढ़ावा दें, विश्वास का निर्माण करें और जोखिमों को कम करें। हम जीएमसी, संयुक्त अभ्यास, औद्योगिक सहयोग, संसाधनों को साझा करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने आदि जैसे संवादों के माध्यम से विश्वास का निर्माण करते हैं। सहयोग करने वाले देशों के बीच साझा समुद्री प्राथमिकताओं में विश्वास जताने से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे।.

इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आईओआर देशों के बीच सहयोग की बात की। आईओआर के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने और संकट के समय में क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की।.

नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अपने संबोधन में बदलते हुए पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों तथा समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीएमसी ऐसे खतरों के खिलाफ प्रभावी शमन

रणनीतियों को विकसित करने की दिशा में एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है, जिससे शांति बनाए रखी जा सके और आईओआर में विकास सुनिश्चित किया जा सके।

अपने मुख्य भाषण के बाद, रक्षा मंत्री ने आयोजन स्थल पर लगाए गए 'मेक इन इंडिया' स्टॉलों का दौरा किया, ताकि 12 देशों के गणमान्य व्यक्ति अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों और प्लेटफार्मों के स्वदेशी निर्माण द्वारा भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमताओं की एक झलक देख सकें।

- आईओआर में समुद्री सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नियामक और कानूनी ढांचे में अंतराल की पहचान करना।
- समुद्री खतरों और चुनौतियों के सामूहिक शमन के लिए जीएमसी देशों के लिए एक सामान्य बहुपक्षीय समुद्री रणनीति और परिचालन प्रोटोकॉल तैयार करना।
- आईओआर में उत्कृष्टता केंद्र के साथ सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान और स्थापना।
- सामूहिक समुद्री दक्षताओं को उत्पन्न करने की दिशा में आईओआर में मौजूदा बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से की गई गतिविधियों का लाभ उठाना।

एबीबी/एसएस